EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay

Useful For Prelims

Date: 12 - 11 - 2025

राष्ट्रपति मुर्मू बोत्सवाना पहुंचीं, चीता स्थानांतरण मुख्य एजंडा

गोबोरोने, 11 नवंबर (भाषा) ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को अपनी दो राष्ट्रों की अफ्रीका यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना पहुंचीं। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करना और भारत में चीतों के स्थानांतरण पर अंतिम समझौते पर मुहर लगाना है।

अंगोला की राजधानी लुआंडा से उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू बोत्सवाना की राजधानी गोबोरोने स्थित सर सेरेटस खामा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं, जहां उनका स्वागत राष्ट्रपति डुमा गिदोन बोको ने किया। उन्हें 21 तोपों की सलामी और गार्ड आफ आनर प्रदान किया गया। अंगोला की भांति, किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष राष्ट्रपति बोको के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय वार्ता करेंगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिये कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान संभावित है। बुधवार को वह बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा के सांसदों को भी संबोधित करेंगी।

इस यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम आठ चीतों को क्वारंटाइन सुविधा में छोड़े जाने का साक्षी बनना होगा। यह घटना वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना द्वारा भारत को इन शिकारी जीवों के प्रतीकात्मक सुपुर्दगी को चिन्हित करेगी। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, यह यात्रा बोत्सवाना के साथ भारत के पुराने और मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार को अपनी छह दिवसीय यात्रा समाप्त कर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी।

Jansatta Page No-16

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा

भारत से व्यापार समझौता करने के करीब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, भारत के साथ 'न्यायसंगत व्यापार समझौते' पर पहुंचने के काफी करीब है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) को 'एक समय' कम कर देंगे। यह दो हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद जताई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त बयान ट्रंप का सामान्य अतिशयोक्तिपूर्ण बयान था या दोनों पक्षों के बीच बहुप्रतीक्षित समझौते के लिए वार्ता में कुछ प्रगति हुई है।

कहा, वह भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) को 'एक समय' कम कर देंगे। *प्रधानमंत्री* नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के शानदार संबंध हैं।

ट्रंप ने सोमवार को कहा कि हम भारत के साथ एक समझौता कर रहे हैं, यह पहले की तुलना में बहुत अलग है। इसलिए अभी वे मुझे पसंद नहीं करते लेकिन वे हमें फिर से पसंद करेंगे। उन्होंने 'ओवल आफिस' में एक कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में शपथ दिलाई। ट्रंप ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा साझेदार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के शानदार संबंध हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शानदार संबंध हैं और सर्जियो गोर ने इस रिश्ते को और मजबूत किया है क्योंकि वह पहले से ही प्रधानमंत्री के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं। जब उन्हें पता चला कि सर्जियो भारत के राजदूत बनने वाले हैं तो वे लगातार संपर्क में रहते थे कि 'आइए, इस व्यक्ति को जानें।' और उन्हें सर्जियो पसंद आए। ट्रंप ने कहा कि हम एक उचित समझौता कर रहे हैं, सिर्फ एक न्यायसंगत व्यापार सौदा। पहले हमारे पास काफी अनुचित व्यापार समझौते थे। भारत के लोग बहुत अच्छे वार्ताकार हैं, सर्जियो, इसलिए इस पर ध्यान रखना होगा।

Jansatta Page No-16

'भारत व न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी'

नई दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा)।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में व्यापार वार्ता को गति देने के लिए न्यूजीलैंड गए थे। अधिकारी ने कहा कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है...। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचाने में कुछ और सप्ताह लग सकते हैं।

उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टाड मैक्ले शुक्रवार को व्यापार वार्ता के लिए यहां आएंगे। मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत औपचारिक रूप से 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई थी। भारत का न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2024-25 में 1.3 अरब डालर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 49 फीसद की वृद्धि है।

अधिकारी ने यह भी कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) भी भारत के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के लिए उत्सुक है। बहरीन और कतर पहले ही अलग-अलग एक व्यापार समझौते में रुचि दिखा चुके हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। भारत ने यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को लागू किया है।

Jansatta Page No-10

अब तक का सर्वाधिक 68.79 फीसद मतदान

मतदाताओं की भागीदारी 74.03 फीसद रही, जबकि पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 64.1 फीसदी रही। निर्वाचन आयोग ने कहा कि डेटा अनंतिम है और इसमें सेवा मतदाता, ट्रांसजेंडर मतदाता और डाक मतपत्रों का आंकड़ा नहीं है। इससे पहले छह नवंबर को भी पहले चरण में सर्वाधिक 65.09 फीसद मतदान था, जो कि आज लगभग दो फीसद अधिक है।

अधिकारियों ने कहा कि कई मतदान केंद्रों पर शाम तक लंबी कतारें देखी गईं, इसलिए अंतिम मतदान प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। सबसे अधिक मतदान कटिहार, किशनगंज, पूर्णियां, पूर्वी चंपारण व सपौल जिलों में दर्ज किया गया है। कटिहार जिले में 78.84 और किशनगंज में 78.15 फीसद मतदान दर्ज किया गया है। आयोग के मुताबिक बिहार के चुनाव में इस बार 1951 के बाद सार्वधिक मतदान दर्ज किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक मतदान फीसद लगभग 66.9 है। हमारी माताओं और बहनों ने चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा जताया है और 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सबसे ज्यादा 71 फीसद मतदान दर्ज किया है।

बिहार में हुए इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगानिर्वाचन आयोग के आंकड़े के मुताबिक दूसरे चरण में कुल 37013556 मतदाता थे, इन मतदाताओं में से 17468572 महिला और 19544041 पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जबकि पहले चरण में कुल 37513302 कुल मतदाता थे, इनमें 17677219 महिला और 19835325 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

इस प्रकार दोनों ही चरणों में इस बार महिलाएं मतदान के लिए आगे आई हैं। आयोग के मुताबिक इस मतदान के लिए करीब 8.5 लाख मतदान कर्मचारियों का सहयोग लिया गया है। इन दोनों ही चरणों में मतदाताओं ने 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवारों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये चुनाव बिहार के 38 जिलों में सम्पन्न कराए गए हैं।

Jansatta Page No-9

छियासी फीसद किसान कृषि प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण से दूर

जनसत्ता ब्यूरो

भा रपट

रत को प्रौद्योगिकी से अभी भी अछूते अधिकांश किसानों तक पहुंचने के लिए खंडित कृषि नवाचार से हटकर राज्य-स्तरीय परीक्षण मंच और एकीकृत डेटा ढांचे के माध्यम से प्रणालीगत एकीकरण की ओर बढ़ना होगा। उद्योग मंडल एसोचैम की मंगलवार को जारी एक रपट में यह बात कही गई है।

उद्योग निकाय ने कहा कि 86 फीसदी किसान अभी भी अधिकांश कृषि-प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण की पहुंच से बाहर हैं और प्रौद्योगिकी के सत्यापन, व्यावसायीकरण और छोटे किसानों तक उनकी पहुंच के तरीके में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। रपट में कहा गया, भविष्य के लिए तैयार कृषि प से परिभाषित होगी कि वह प्रौद्योगिकी को समावेशन के साथ, डेटा को निर्णय लेने के साथ और नवाचार को प्रभाव के साथ कितनी प्रभावी ढंग से एकीकृत करता है। एसोचैम की रपट में वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए सहयोगी परीक्षण स्थल के रूप में काम करने को राज्य-स्तरीय कृषि-तकनीकी सैंडबाक्स स्थापित करने की सिफारिश की गई है। प्रस्तावित सैंडबाक्स सरकारी एजेंसियों, नवोन्मेषण और अनुसंधान संस्थानों को पूर्ण पैमाने पर तैनाती से पहले समाधान को सत्यापित करने के लिए एक साथ लाएंगे। रपट में कहा गया है कि 90 से ज़्यादा आईसीएआर संस्थान, 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) होने के बावजूद, भारत में उभरती कृषि प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए एक एकीकृत प्रणाली का अभाव है।

वर्तमान तंत्र खंडित और धीमा बना हुआ है, जिससे नवाचार के लिए स्पष्ट सत्यापन के रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं। प्रत्येक सैंडबआक्स राज्य कृषि विभागों के भीतर स्थापित होगा, जिसमें आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और नाबार्ड सहित संबद्ध विभागों और भागीदारों की हिस्सेदारी होगी। कृषि मंत्रालय और नीति आयोग की सह-अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति शासन और वित्तपोषण की देखरेख करेगी।

Jansatta Page No-7

जल संचय जन भागीदारी में तेलंगाना का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ

जनसत्ता ब्यूरो

जल संचय जन भागीदारी में तेलंगाना राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य-केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर रहा। वहीं इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा।

दरअसल, मंगलवार को जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रथम पुरस्कारों की घोषणा की। विज्ञान भवन में इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 नवंबर को प्रथम जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल शक्ति के लिए जन शक्ति के दृष्टिकोण से प्रेरित, जल संचय जन भागीदारी पहल 6 सितंबर 2024 को सूरत में आरंभ की गई थी। पहल के तहत राज्यों को पांच क्षेत्रों में विभाजित कर कम से कम दस हजार कृत्रिम पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के जिलों के लिए यह लक्ष्य तीन हजार है, जबकि देश भर के नगर निगमों के लिए यह दस हजार का लक्ष्य है। इन संरचनाओं में भवन छतों पर वर्षा जल संचयन के साथ ही झीलों, तालाबों और बावड़ियों का पुनरुद्धार करना शामिल है।

प्रथम जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) सम्मान के तहत इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें तीन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, 67 जिले, छह नगर निगम, एक शहरी स्थानीय निकाय, दो सहयोगी मंत्रालय/विभाग, दो उद्योग, तीन गैर सरकारी संगठन, दो परोपकारी और 14 नोडल अधिकारी शामिल हैं। जेएसजेबी पोर्टल पर अपलोड किए गए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है। इस कार्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्रेणी एक के जिलों को 2 करोड़ रुपए प्रति जिले से पुरस्कृत किया जा रहा है, जबकि श्रेणी दो और तीन के जिलों को क्रमशः एक करोड़ रुपए प्रति जिले और 25 लाख रुपए के पुरस्कार दिये जाएंगे। अन्य जिलों को भी प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया जा रहा है।

छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मंगलवार को श्रम शक्ति भवन में छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की सूची की घोषणा की। राष्ट्रपति की उपस्थिति में 18 नवंबर को ये पुरस्कार 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे। इस बार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी के साथ-साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं की घोषणा की गई है।

उपलब्धि

प्रथम जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) सम्मान के तहत इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें तीन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, 67 जिले, छह नगर निगम, एक शहरी स्थानीय निकाय, दो सहयोगी मंत्रालय/विभाग, दो उद्योग, तीन गैर सरकारी संगठन, दो परोपकारी और 14 नोडल अधिकारी शामिल हैं।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मंगलवार को श्रम शक्ति भवन में छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की सूची की घोषणा की। राष्ट्रपति की उपस्थिति में 18 नवंबर को ये पुरस्कार 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे। इस बार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।

खतरे का तापमान

जलवायु परिवर्तन से उपजे संकट से निपटने के लिए वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर पेरिस में एक महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था। मगर इस समझौते में जताई गई प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रयास होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि, विकासशील देश इस दिशा में आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन वित्तीय और तकनीकी चुनौतियां उनकी राह में रोड़े अटका रही हैं। इसके बावजूद भारत और चीन जैसे देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर शुरू हुई 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' की 30वीं वार्षिक बैठक में इन दोनों देशों की परिवर्तनकारी भूमिका की सराहना की गई। साथ ही कहा गया कि इन देशों ने जलवायु कार्रवाई को स्पष्ट तरीके से अपनाया है और वे दुनियाभर में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की लागत कम करने में मदद कर रहे हैं।

दरअसल, पेरिस समझौते में तय हुआ था कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों की वित्तीय और तकनीकी रूप से मदद करेंगे। मगर संयुक्त राष्ट्र की हाल की एक रपट बताती है कि यह वित्तीय मदद लगातार घट रही है। विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर साल 365 अरब डालर की जरूरत है, लेकिन वर्ष 2023 में इन देशों को केवल 26 अरब डालर की अंतरराष्ट्रीय सहायता मिल पाई, जो वर्ष 2022 के 28 अरब डालर से भी कम है। सवाल है कि विकसित देशों ने अपने वादे के अनुसार विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने से अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए हैं? हो सकता है कि इन देशों को इसमें निजी हित नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उनका योगदान सबसे ज्यादा है। इस लिहाज से विकासशील देशों की वित्तीय मदद और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने में उनका तकनीकी तौर पर सहयोग करना विकसित देशों की नैतिक जिम्मेदारी है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि दशकों से इस मसले पर जताई जा रही अंतरराष्ट्रीय चिंता का हासिल अब तक कोई ठोस हल सामने क्यों नहीं ला सका है।

सीओपी30 के अध्यक्ष डो लागो ने कहा

स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे भारत-चीन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

जलवायु परिवर्तन पर 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' की 30वीं वार्षिक बैठक (सीओपी30) के अध्यक्ष आंद्रे कोरेयो डो लागो ने वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत और चीन की परिवर्तनकारी भूमिका की प्रशंसा की और कहा कि दोनों देशों ने जलवायु कार्रवाई को स्पष्ट तरीके से अपनाया है। अध्यक्ष ने कहा कि वे दुनिया में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की लागत कम करने में मदद कर रहे हैं।

ब्राजील के बेलेम शहर में सीओपी30 के उद्घाटन के दौरान आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में लागो ने कहा कि चीन ने इस एजंडे को 'असाधारण तरीके से अपनाया है', जिसमें पैमाना, तकनीक और वहनीयता जैसे तीन प्रमुख तत्वों का संयोजन किया गया है, जिसने पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर प्रगति को तेज किया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में चीन के योगदान को लेकर एक सवाल पर कहा, 'चीन के पास बहुत उन्नत तकनीक है और उसके पैमाने की केवल भारत से तुलना की जा सकती है। और भारत भी किसी न किसी रूप में वही कर रहा है क्योंकि उनके पास भी शानदार कंपनियां, इंजीनियर और बेहतरीन लोग हैं। वे दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।'

लागो ने कहा कि चीन के विशाल उत्पादन पैमाने ने मुख्य हरित प्रौद्योगिकियों की लागत कम करने में मदद की है जिससे पूरे विश्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, 'अब हमारे पास दो बड़े बाजार होंगे जो इस परिवर्तन की लागत को कम करेंगे क्योंकि दोनों देशों ने इस परिवर्तन को बहुत स्पष्ट रूप से अपनाया है।'

आंद्रे ने वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत और चीन की परिवर्तनकारी भूमिका की प्रशंसा की और कहा कि दोनों देशों ने जलवायु कार्रवाई को स्पष्ट तरीके से अपनाया है।

लागो ने कहा कि भारत के पास शानदार कंपनियां, इंजीनियर और बेहतरीन लोग हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास दो बड़े बाजार होंगे (चीन और भारत), जो इस परिवर्तन की लागत को कम करेंगे।

धमाके की जांच एनआइए के हवाले, मोदी ने कहा-दोषियों को बख्शेंगे नहीं

दिल्ली में मरने वालों की संख्या 12, यूएपीए के तहत मामला दर्ज; आतंकी साजिश के कोण से हो रही जांच

जनसत्ता टीम
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) करेगी। इस विस्फोट की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है। वहीं, दो दिन की यात्रा पर भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विस्फोट के साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। इस धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई, जिनमें से चार उत्तर प्रदेश के हैं।

दूसरी ओर, गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजंसियों को निर्देश दिया कि वे इस मामले में संलिप्त प्रत्येक दोषी की तलाश करें। पुलिस ने कहा है कि कार चला रहे पुलवामा के डाक्टर के आतंकवादी माड्यूल से संबंध थे, इस धमाके की आतंकी साजिश कोण से भी जांच की जा रही है।

कार चला रहे पुलवामा के डाक्टर के आतंकवादी माड्यूल से थे संबंध : पुलिस

जांचकर्ताओं ने पुलवामा के एक डाक्टर पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका संबंध मुख्य रूप से फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के साथ पर्दाफाश किए गए एक आतंकी माड्यूल से है। डा उमर नबी उस कार को चला रहा था, जिसमें विस्फोट हुआ और माना जा रहा है कि वह मारे गए 12 लोगों में से एक है। विस्फोट के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर की मां का डीएनए नमूना लिया, ताकि अवशेषों की पुष्टि हो सके। श्रीनगर में एक अधिकारी ने कहा, 'हमने विस्फोट स्थल पर मिले अवशेषों का मिलान करने के लिए डीएनए नमूना लिया है।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह हुई समीक्षा बैठक के बाद यह मामला राष्ट्रीय **बाकी पेज 8 पर**

जांच एजंसियां मामले की तह तक जाएंगी : प्रधानमंत्री

भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की 70वीं जयंती के अवसर पर थिंपू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली विस्फोट के साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना की जांच कर रही एजंसियां मामले की तह तक जाएंगी और इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को न्याय के शिकंजे में लाया जाएगा।

मोदी ने भूटान के पूर्व नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की 70वीं जयंती के मौके पर थिंपू के चांगलीमेथांग स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली की घटना के मद्देनजर वह भारी मन से थिंपू आए हैं। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को पूरी रात विस्फोट की जांच कर रही एजंसियों के संपर्क में रहे। मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच सदियों से गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं।

इसलिए, इस खास मौके का हिस्सा बनना भारत और मेरी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कहा, लेकिन आज मैं भारी मन से यहां आया हूं। सोमवार शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

-पूरी खबर पेज 16

'प्रारंभिक जांच से दुर्घटनावश विस्फोट होने का संकेत मिलता है'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

लाल किले के निकट हुए विस्फोट की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह विस्फोट दुर्घटनावश हो सकता है। दरअसल जल्दबाजी में तैयार किया गया यह विस्फोटक उपकरण एक अंतरराज्यीय आतंकवादी माड्यूल के फरीदाबाद में भंडाफोड़ के बाद ले जाया जा रहा था।

लाल किले के नजदीक सोमवार शाम को हुआ विस्फोट दिल्ली-एनसीआर और जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में कई स्थानों पर सुरक्षा एजंसियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद आतंकियों में फैली घबराहट और हताशा के कारण किया गया हो सकता है। यह आशंका सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती जांच के आधार के पर जताई है।

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छापेमारी की ये गतिविधियां उन संदिग्धों को पकड़ने के लिए की गई थी, जिनके आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा होने की आशंका थी। वरिष्ठ सुरक्षा सूत्रों ने यह भी कहा कि बम समय से पहले ही फट गया था और पूरी तरह तरह से तैयार नहीं था जिसकी वजह से इसका प्रभाव सीमित रहा। सुरक्षा आकलन में कहा गया है कि विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही मौके पर कोई छर्रे या धमाका करने वाले उपकरण मिले।

-पूरी खबर पेज 8

दिल्ली विस्फोट में उत्तर प्रदेश के चार लोगों की गई जान पेज 16

भारत में विशाल बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का निर्माण करेगा अडाणी समूह

नई दिल्ली (भाषा)।

अडाणी समूह ने बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में प्रवेश की मंगलवार को घोषणा की। समूह की गुजरात के खावड़ा में 1,126 मेगावाट/ 3,530 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापित करने की योजना है जो भारत की सबसे बड़ी एवं दुनिया की सबसे बड़ी एकल-स्थान भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी।

समूह ने बयान में कहा कि 700 से अधिक बीईएसएस कंटेनर वाली इस सुविधा के मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। यह खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर का हिस्सा होगी जिसे विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र बताया जा रहा है। बीईएसएस परियोजना की विद्युत क्षमता 1126 मेगावाट और ऊर्जा क्षमता 3530 मेगावाट होगी। इसका मतलब है कि

बीईएसएस 3530 मेगावाट ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम होगी जिससे 1126 मेगावाट की विद्युत क्षमता लगभग तीन घंटे बढ़ जाएगी। अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा, 'ऊर्जा भंडारण अक्षय ऊर्जा आधारित भविष्य की आधारशिला है। इस ऐतिहासिक परियोजना के साथ, हम न केवल वैश्विक मानक स्थापित कर रहे हैं बल्कि भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता एवं स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि यह पहल समूह को बड़े पैमाने पर विश्वसनीय, स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। समूह ने बयान में कहा कि वह वित्त वर्ष 2026-27 तक अपनी भंडारण क्षमता को 15 गीगावाट घंटा और पांच वर्ष के भीतर 50 गीगावाट घंटा तक बढ़ाने की योजना बना रहा है जो बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में उसकी महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है।

Rashtriya Sahara Page No-11

86% किसानों की पहुंच में नहीं हैं कृषि प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण

नई दिल्ली (भाषा)।

भारत को प्रौद्योगिकी से अभी भी अछूते अधिकांश किसानों तक पहुंचने के लिए खंडित कृषि नवाचार से हटकर राज्य-स्तरीय परीक्षण मंच और एकीकृत डेटा ढांचे के माध्यम से प्रणालीगत एकीकरण की ओर बढना होगा। उद्योग मंडल एसोचैम की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। उद्योग निकाय ने कहा कि 86 प्रतिशत किसान अभी भी अधिकांश कृषि-प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण की पहुंच से बाहर हैं, और प्रौद्योगिकी के सत्यापन, व्यावसायीकरण और छोटे किसानों तक उनकी पहुंच के तरीके में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में कहा गया, 'भविष्य के लिए तैयार कृषि प्रणाली की ओर भारत की यात्रा इस बात से परिभाषित होगी कि वह प्रौद्योगिकी को समावेशन के

साथ, डेटा को निर्णय लेने के साथ और नवाचार को प्रभाव के साथ कितनी प्रभावी ढंग से एकीकृत करता है।' एसोचैम की रिपोर्ट में वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए सहयोगी परीक्षण स्थल के रूप में काम करने को राज्य-स्तरीय कृषि-तकनीकी सैंडबॉक्स स्थापित करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 90 से ज़्यादा आईसीएआर संस्थान, 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 700 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) होने के बावजूद, भारत में उभरती कृषि प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए एक एकीकृत प्रणाली का अभाव है। वर्तमान तंत्र खंडित और धीमा बना हुआ है, जिससे नवाचार के लिए स्पष्ट सत्यापन के रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं।

Rashtriya Sahara Page No-11

प्रत्यक्ष कर संग्रह में सात फीसद तक का इजाफा

■ अब तक 12.92 लाख करोड़ का संग्रह

नई दिल्ली (भाषा)।

कॉरपोरेट कर संग्रह में वृद्धि और धीमी रिफंड दर के कारण चालू वित्त वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सात प्रतिशत बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस साल एक अप्रैल से 10 नवंबर के बीच रिफंड जारी करने की दर 18 प्रतिशत घटकर 2.42 लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी।

इस अवधि में शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह लगभग 5.37 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान 5.08 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष में अब तक व्यक्तियों और एचयूएफ सहित गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह लगभग 7.19 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में लगभग 6.62 लाख करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन अवधि में अब तक प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) संग्रह 35,682 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में लगभग 35,923 करोड़ रुपये था।

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं, चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढकर 12.92 लाख करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी अवधि में यह लगभग 12.08 लाख करोड़ रुपये था। रिफंड समायोजित करने से पहले, सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक 15.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 2.15 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने प्रत्यक्ष कर संग्रह 25.20 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो सालाना आधार पर 12.7 प्रतिशत अधिक है।

सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में एसटीटी से 78,000 करोड़ रुपये जुटाना है। डेलॉयट इंडिया के भागीदार रोहिंटन सिधवा ने कहा कि आंकड़े दशति हैं कि पिछले साल ब्याज दरों में भारी कटौती के बावजूद गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि जारी है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है, जो आय स्तर में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

Rashtriya Sahara Page No-11

हरित हाइड्रोजन क्षमता हासिल कर लेगा भारत

नई दिल्ली (भाषा)। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से 2030 तक 50 लाख टन (एमएमटी) वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य से चूक सकता है। हालांकि वह इसे 2032 तक हासिल कर लेगा। हरित हाइड्रोजन सम्मेलन के तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करते हुए सारंगी ने कहा, 'हम लक्ष्य (2030 तक 50 लाख टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता ग्रीन हाइड्रोजन) से पीछे रह सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि देश 2032 तक 50 लाख टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने 2030 तक हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, " भारत 2030 तक 30 लाख टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल कर सकता है।' वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की वार्षिक आवश्यकता के बारे में सारंगी ने कहा कि भारत बिजली खरीद या बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए पहले से ही लंबित 40 गीगावाट क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 160 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर साल कम से कम 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़नी होगी।

Rashtriya Sahara Page No-11

इलाज के लिए भारत आने वालों को मिल सकती है 'वीजा ऑन अराइवल' सुविधा

■ किन देशों के मरीजों को दी जा सकती है यह सुविधा इस पर विचार करेगी सरकार : गोयल

नई दिल्ली (भाषा)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका जैसे देशों के मरीजों को चिकित्सकीय उपचार के लिए आगमन पर वीजा (वीजा ऑन अराइवल) की सुविधा देने पर विचार किया जा सकता है।

गोयल ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में कहा, 'आगमन पर वीजा का विचार अच्छा है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। कई देशों के लिए हम आगमन पर वीजा की अनुमति देते है। हम ई-वीजा की अनुमति भी देते है। इन दोनों पर विचार किया जा सकता है। अमेरिका के लिए, अधिकतर यूरोपीय देशों के लिए। वैसे सभी के लिए नहीं। अधिकतर देशों के लिए जहां हमें काफी सुविधा है और जहां विस्तृत जांच-पड़ताल या पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।'

उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ को इस विचार पर काम करने और सरकार के साथ साझा करने का सुझाव दिया। गोयल ने कहा, 'जाहिर है हमें यह देखना होगा कि क्या प्रमाणन होंगे और वे कौन से देश है जिनके लिए हम इसकी अनुमति दे सकते है।'

भारत व्यापार समझौतों में किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा : गोयल

नई दिल्ली (भाषा)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत व्यापार समझौतों में किसानों, डेयरी और श्रमिकों के हितों से समझौता नही करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रूस जैसे नए बाजारों की तलाश कर रहा है, जो अमेरिका में भारी शुल्क के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने यहां उद्योग समागम-2025 में कहा, " हम एक अच्छे व्यापार समझौते के लिए काम कर रहे है। भारत किसानों, डेयरी और श्रमिकों के हितों से समझौता नहीं करेंगेज हम एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित व्यापार समझौते पर काम कर रहे है।' यह राज्यों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों का सम्मेलन है। मंत्री ने कहा, 'यह (व्यापार समझौता) कल हो सकता है, अगले महीने हो सकता है, अगले साल हो सकता है।

Rashtriya Sahara Page No-11

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 'डिजिटल लेबर चौक' ऐप की शुरुआत की

श्रमिकों को ऐप से काम की जानकारी मिलेगी

योजना

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। निर्माण व अन्य कार्यों से जुड़े श्रमिकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप शुरू किया। इसके माध्यम से श्रमिक अपने अनुभव और जरूरत के हिसाब से अपने स्थानीय इलाकों में ही काम ढूंढ पाएंगे।

मंगलवार को भारत मंडपम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ऐप और सेस क्लेक्शन पोर्टल की शुरुआत की। यह कई भाषाओं में उपलब्ध है, जो कुशल श्रमिकों को नियोक्ताओं से डिजिटल रूप से जोड़ता है। ऐप के जरिए श्रमिकों और नियोक्ताओं को पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। श्रमिक अपना नाम, उम्र, अपना पता, मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालकर पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही अपने कौशल से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। उसके बाद पूरी प्रोफाइल बनकर तैयार होगी। इसी तरह से नियोक्ताओं को अपने, प्रोजेक्ट और किस तरह के श्रमिकों की जरूरत है, उसकी जानकारी ऐप पर दर्ज करनी होगी। इससे श्रमिक जरूरत के हिसाब से निकट क्षेत्र में काम खोज पाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने देशभर में तीन लाख से अधिक लेबर चौक को सुविधा श्रमिक केंद्र के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि वर्तमान में सड़क किनारे संचालित होने वाले इन चौक पर सड़क दुर्घटना से लेकर तमाम सारे खतरे हैं। इसलिए जिन लेबर चौक पर श्रमिक ज्यादा आता है और आस-पास कहीं जगह अधिक है तो वहां उन्नत लेबर चौक सुविधा केंद्र बनाया जाए।

घर बैठे पसंद का काम चुन सकेंगे

यह ऐप अर्बन क्लैप की तरह है। श्रमिक लेबर चौक आने की जगह ऐप के जरिए घर बैठे ही अपनी पसंद का काम चुन कर जा सकेंगे। इससे लेबर चौक पर लगने वाली भीड़ से भी राहत मिलेगी। इसी तरह से सेस क्लेक्शन पोर्टल पर हर प्रोजेक्ट का पूरे विवरण के साथ पंजीकरण कराना होगा, जिसमें राज्यों को निर्माण कार्यों से होने वाले सेस क्लेक्शन को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी।

सुविधा केंद्रों में यह व्यवस्था होगी

एक पक्की इमारत बनाई जाएगी, जिसमें बिजली-पानी, इंटरनेट, श्रमिकों के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, कौशल विकास ट्रेनिंग जैसे सहूलियतें होंगी। महिला श्रमिकों के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी।

Hindustan Page No-15

अभूतपूर्वः दूसरे चरण में 69 फीसदी वोट पड़े

67% से अधिक औसत मतदान हुआ दोनों चरणों को मिलाकर राज्य में इस बार

बिहार में मतदान का कीर्तिमान

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधानसभा के दूसरे एवं अंतिम चरण में मतदाताओं ने नया कीर्तिमान बनाया। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़ मंगलवार शाम छह बजे तक रिकॉर्ड 69.12% मतदान हुआ है। यह पहले चरण के मुकाबले 4.04 फीसदी अधिक है। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

दोनों चरणों को मिलाकर बिहार में 67.10 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले। यह 2020 के चुनाव के 57.29 फीसदी के मुकाबले 9.81% अधिक है। यह बिहार में अब तक हुए सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक है। पहले चरण में भी रिकॉर्ड 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो अबतक का सर्वाधिक था। इन सारे रिकॉर्ड को दूसरे चरण के वोटरों ने ध्वस्त कर दिया।

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में 69.04 फीसदी महिलाओं और 61.56 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया था। दूसरे चरण में 74.03 प्रतिशत महिलाओं और 64.1 प्रतिशत पुरुषों ने वोट डाले। दोनों चरणों को मिलाकर 71.6 प्रतिशत महिलाओं और 62.8 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया। दूसरे चरण में कटिहार में सर्वाधिक 79.10 , जबकि, सबसे कम नवादा में 57.86 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया।

कुछ आंकड़े आने बाकी: मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य में दोनों चरणों में पहली बार सभी बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की निगरानी की गई। दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर दोनों चरणों का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद अभी करीब दो हजार बूथों से आंकड़ों का संग्रह होना शेष है।

दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में बंदः दूसरे चरण के मतदान के साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार एवं लोजपा (आर) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित 1302 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया।

कुल 45,399 मतदान केंद्रः दूसरे चरण में कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चरण में नक्सल प्रभावित सात विधानसभा क्षेत्रों चैनपुर, रजौली (सु), गोविंदपुर, सिकंदरा (सु), जमुई, झाझा एवं चकाई एवं 1202 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान हुआ। नक्सल इतिहास वाले जिलों में कई बूथों पर दो दशकों बाद पहली बार मतदान हुआ। जमुई के चोरमारा में दो दशक के बाद ग्रामीणों ने अपने बूथ पर मतदान किया। मतदान के दौरान कुल 990 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं 10 वाहनों को जब्त किया गया।

देखें P 2,4,5,6,7,8,9

2020 चुनाव के मुकाबले इस बार 9.81 फीसदी अधिक वोटिंग

अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाथे में मंगलवार को मतदान के लिए महिला और पुरुषों की लगी कतार। ● अरुण अधि

महिलाओं ने पुरुषों से नौ फीसदी अधिक मतदान किया

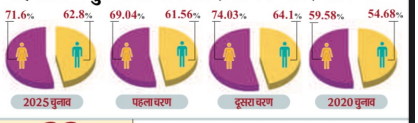

बिहार चुनाव भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक मील का पत्थर है। मतदाताओं ने 1951 के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान किया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी चुनाव कर्मियों और राजनीतिक दलों के एजेंटों की मदद से संभव हो पाई।

-ज्ञानेश कुमार, सीईसी

मतदान में ये 5 जिले अव्वल

इन 5 जिलों में सबसे कम

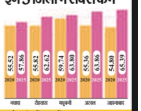

दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े (%)में

77 फीसदी मतदान हुआ था केरल विस चुनाव में 2016 में

84 फीसदी वोटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव में लक्षद्वीप में

चुनाव के दौरान खास बातें

- पूर्णिया जिले के कसबा में सबसे अधिक 80.89 प्रतिशत मतदान हुआ
- पश्चिम चंपारण के रामनगर क्षेत्र के 24 गांवों के लोगों ने वोट बहिष्कार किया
- अरवल मनेरी बिगहा बूथ पर तैनात मतदानकर्मी की हार्टअटैक से मौत
- गया, रोहतास और जमुई जिले के 14 गांवों में ढाई दशक बाद बूथ बनने से उत्साह दिखा

2020 चुनाव में जीते

Hindustan Page No-1

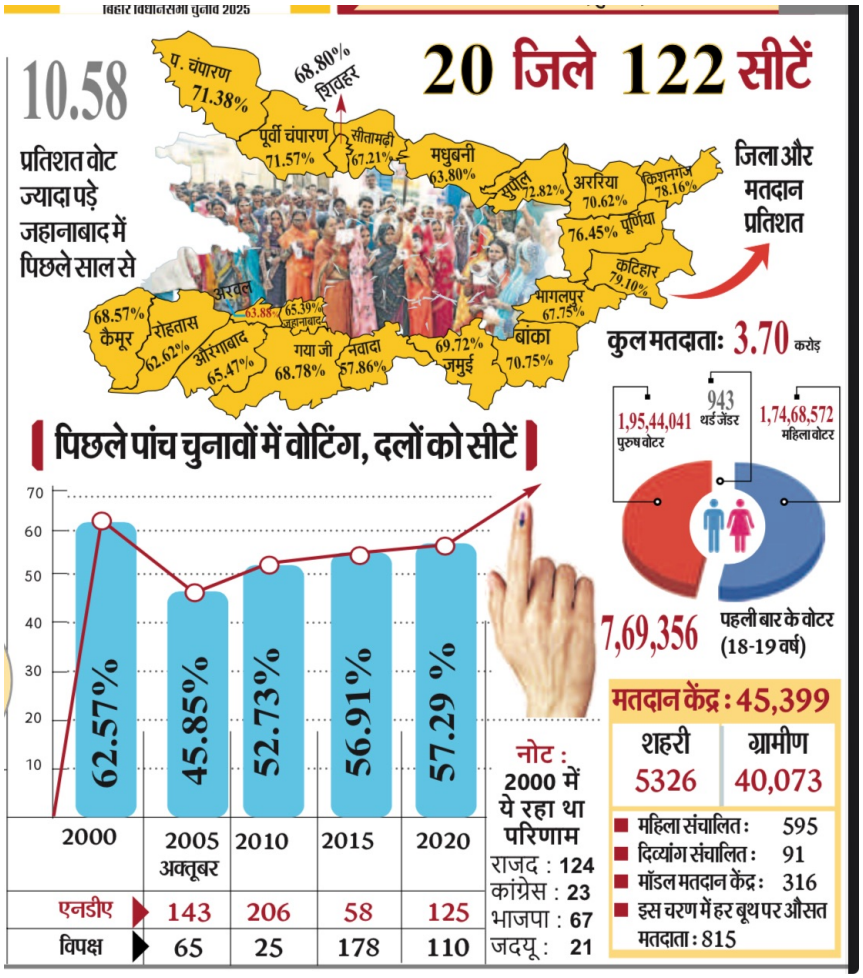

Hindustan Page No-2

Useful For Mains

प्रदूषण की फिक्र के बीच बढ़ता संकट

दिल्ली का प्रदूषण जमीनी समस्या है। इसका समाधान जमीन पर प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को बंद करने से होगा। कृत्रिम बारिश प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं है। यह एक 'आपातकालीन' उपाय है, जिसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब मौसम की सभी परिस्थितियां अनुकूल हों।

रंजना मिश्रा

दिल्ली का आसमान जब धुएं और धूल की एक मोटी चादर ओढ़ लेता है, तब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज सिर्फ धुंधला-सा एक धब्बा बन कर रह जाता है। तब हर किसी को बारिश की प्रतीक्षा होती है। एक ऐसी बारिश की जो जहरीले गुबार को धो डाले और हवा को फिर से सांस लेने लायक बना दे। यह वह स्थिति होती है जब स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, अस्पतालों में सांस के मरीजों की कतारें लग जाती हैं और स्वस्थ इंसान भी अपनी आंखों में जलन और फेफड़ों में चुभन महसूस करने लगता है। मगर जब प्रकृति रूठ जाती है, जब मानसून दूर होता है और पश्चिमी विक्षोभ भी धोखा दे जाता है, तब नजरें उठती हैं विज्ञान की ओर।

प्रदूषण से लड़ाई की इसी उम्मीद के साथ कुछ समय पहले दिल्ली ने कृत्रिम बारिश के लिए बादलों का दरवाजा खटखटाया था। आइआइटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ मिल कर एक बड़ी योजना बनी। विशेष विमान तैयार किए गए और दिल्ली की बेबस जनता टकटकी लगाए आसमान की ओर देखने लगी। वह दिन आया, जब विमानों ने बादलों के बीच जाकर अपना काम किया। मगर नतीजा सिफर रहा। यह महंगा तकनीकी प्रयोग विफल रहा। इस नाकामी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कृत्रिम बारिश आखिर होती कैसे है?

कृत्रिम बारिश को वैज्ञानिक भाषा में 'क्लाउड सीडिंग' या 'बादलों का बीजारोपण' कहते हैं। यह पहले से मौजूद बादलों को बारिश करने के लिए 'मनाने' या 'उकसाने' की एक तकनीक है। प्राकृतिक तौर पर बारिश तब होती है, जब बादलों में मौजूद पानी की अरबों सूक्ष्म बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल आपस में जुड़ कर इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें और संभाल नहीं पाती और वे गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरने लगते हैं। यह प्रक्रिया उन घने 'कपासी' बादलों में सबसे अच्छी होती है जो रुई के पहाड़ों की तरह दिखते हैं और जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है। मगर कई बार, बादलों में पानी तो बहुत होता है, मगर वे बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि आपस में जुड़ कर भारी नहीं हो पातीं। यहीं पर बादलों के बीजारोपण की भूमिका शुरू होती है।

इस प्रक्रिया में, एक विमान या राकेट के जरिए बादलों के एक खास हिस्से में कुछ विशेष रसायन छोड़े जाते हैं। ये रसायन 'बीज' का काम करते हैं। सबसे आम रसायन है सिल्वर आयोडाइड, जिसकी बनावट बर्फ के बारीक टुकड़े से मिलती है। जैसे ही इसे ठंडे बादलों में छिड़का जाता है, पानी की ठंडी बूंदें इसे असली बर्फ के टुकड़े समझ कर इससे चिपकने लगती हैं। देखते ही देखते यह छोटा सा कण लाखों बूंदों को जोड़ कर बर्फ का एक बड़ा 'क्रिस्टल' बन जाता है, जो पिघल कर बारिश की बूंद के रूप में जमीन पर गिरता है। गर्म बादलों के लिए, नमक या कैल्शियम क्लोराइड जैसे 'नमी सोखने वाले' कणों का इस्तेमाल होता है, जो हवा से नमी खींच कर बड़ी बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। यह तकनीक कोई नई नहीं है। चालीस के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट शेफर ने इसकी खोज की थी और तब से लेकर आज दुनिया के पचास से अधिक देश इसका इस्तेमाल सूखे से लड़ने और पानी के भंडारण के लिए या यहां तक

कि बड़े आयोजनों से पहले मौसम साफ करने के लिए करते आ रहे हैं।

अब सवाल यह है कि यह तकनीक दिल्ली में क्यों नाकाम हो गई? इसका जवाब है, नमी। दिल्ली का यह प्रयोग इसलिए विफल नहीं हुआ कि वैज्ञानिकों ने कोई गलती की या विमान ठीक से नहीं उड़े या सिल्वर आयोडाइड ने काम नहीं किया। यह प्रयास इसलिए नाकाम हुआ कि जिस 'कच्चे माल' की इस तकनीक को सबसे अधिक जरूरत होती है, वही आसमान से गायब था। आइआइटी कानपुर के विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि कृत्रिम बारिश की सफलता के लिए बादलों में नमी की एक न्यूनतम मात्रा होना अनिवार्य है। सीधे शब्दों में कहें, तो बादल 'गीले' और घने होने चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार, एक सफल बीजारोपण के लिए बादलों में कम से कम 50 फीसद या उससे अधिक तरलता होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्य से, जिस दिन दिल्ली में यह परीक्षण किया गया, उस दिन आसमान में जो बादल मौजूद थे, वे बहुत पतले, सूखे और बेजान थे। वे घने कपासी बादल नहीं थे। उनमें नमी की मात्रा सिर्फ दस से बीस फीसद के बीच पाई गई। यह उस सूखी 'स्पंज' की तरह था, जिसे कितना भी निचोड़ लें, उसमें से पानी नहीं निकल सकता।

> जब तक करोड़ों वाहन धुआं उगलते रहेंगे, जब तक निर्माण स्थलों से धूल उड़ती रहेगी और जब तक औद्योगिक इकाइयां जहरीली हवा छोड़ती रहेंगी, तब तक कोई भी कृत्रिम बारिश हमें बचा नहीं सकती। हमें अपनी जीवनशैली, अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को बदलना होगा। हमें सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना होगा, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना होगा। प्रदूषण के खिलाफ एक सख्त और ईमानदार जंग लड़नी होगी। दिल्ली में प्रदूषण का गहराता संकट एक चेतावनी है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रित करने का वहम पालना छोड़ देना चाहिए। समाधान ऊपर आसमान में नहीं, नीचे जमीन पर है।

विडंबना देखिए, जिस प्रदूषण को मिटाने के लिए यह बारिश कराई जा रही थी, शायद उसी प्रदूषण ने बादलों की संरचना को इस हद तक बिगाड़ दिया था कि वे कृत्रिम बीजारोपण के लिए भी तैयार नहीं थे। वैज्ञानिकों को सिर्फ सूखे बादलों से ही नहीं, बल्कि 'प्रदूषित' और 'बिगड़ैल' बादलों से भी निपटना था। विमानों ने बादलों में सिल्वर आयोडाइड दागे, उन रसायनों ने अपना काम करने की कोशिश भी की, लेकिन जब बादलों में पर्याप्त जल कण ही नहीं थे, तो वे आपस में जुड़ कर बड़ी बूंदें कैसे बनाते? जो थोड़े-बहुत कण बने भी, वे इतने हल्के थे कि जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बन गए। इस विफलता का एक और तकनीकी कारण था बादलों की ऊंचाई। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि बादल पांच हजार फुट के आसपास यानी जमीन के करीब होते, तो सफलता की संभावना ज्यादा होती, लेकिन दिल्ली के ऊपर बादल करीब दस हजार फुट या उससे भी अधिक ऊंचाई पर थे। इतनी ऊंचाई से एक छोटी बूंद का जहरीली और गर्म हवा के थपेड़ों को झेल कर जमीन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा, दिल्ली की सर्दियों में 'तापमान व्युत्क्रमण' की एक मोटी परत बन जाती है, जिसमें ठंडी हवा नीचे फंस जाती है और गर्म हवा उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देती है। यह ढक्कन ही सारे प्रदूषण को शहर के ऊपर कैद रखता है। कृत्रिम बारिश के इस प्रयोग का एक मकसद इस ढक्कन को तोड़ना भी था, लेकिन अपर्याप्त नमी के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका।

कृत्रिम बारिश प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं है। यह एक 'आपातकालीन' उपाय है, जिसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब मौसम की सभी परिस्थितियां, खासकर नमी सौ फीसद अनुकूल हों। दरअसल, दिल्ली का प्रदूषण जमीनी समस्या है। इसका समाधान बादलों में सिल्वर आयोडाइड छिड़कने से नहीं, बल्कि जमीन पर प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को बंद करने से होगा। जब तक करोड़ों गाड़ियां धुआं उगलती रहेंगी, जब तक निर्माण स्थलों से धूल उड़ती रहेगी और जब तक औद्योगिक इकाइयां जहरीली हवा छोड़ती रहेंगी, तब तक कोई भी कृत्रिम बारिश हमें बचा नहीं सकती। हमें अपनी जीवनशैली, अपनी नीतियों और अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। हमें सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना होगा, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना होगा। प्रदूषण के खिलाफ एक सख्त और ईमानदार जंग लड़नी होगी। दिल्ली में प्रदूषण का गहराता संकट एक चेतावनी है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रित करने का वहम पालना छोड़ देना चाहिए। समाधान ऊपर आसमान में नहीं, नीचे जमीन पर है।

Jansatta Page No-6

अधूरे अनुबंधों की यात्रा

मनीषा मंजरी

समय की धारा में बहती यह जिंदगी न जाने कितने ही अजनबी मोड़ से होकर गुजरती है। कभी ये मोड़ हमें किसी शांत तट तक ले आते हैं, जहां मन ठहर जाने को आतुर हो उठता है। लगता है कि यही वह स्थान है, जहां इस यात्रा को रुक जाना चाहिए। मगर जीवन की यह धारा किसी एक ठहराव को स्थायी नहीं बनने देती, वह आगे बहती रहती है। नए किनारे दिखाती है, नए अनुभवों का उपहार देती है, जो कभी सुखद होते हैं, तो कभी असहनीय।

इस जीवन धारा में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जो हमें उस समय समझ नहीं आते। कुछ अप्रासंगिक, कुछ रहस्यमय और कुछ ऐसे, जिनका अर्थ हमारे वर्तमान बोध से बहुत परे होता है। ये वे क्षण होते हैं, जब हमें किसी गहरे पूर्वानुभव का एहसास होता है। किसी अनजाने व्यक्ति की मुस्कान, किसी पुराने गीत की धुन, किसी जगह की गंध या किसी दृश्य का अचानक भीतर तक उतर जाना। ऐसा लगता है मानो आत्मा ने यह सब पहले जिया हो। कहीं, किसी और समय में। ऐसे पूर्वानुभव हमें अक्सर उलझन में डाल देते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी परतें धीरे-धीरे खुलने लगती हैं। तब समझ आता है कि ये घटनाएं संयोग नहीं थीं, ये हमारी आत्मा की यात्रा के संकेत थे। अदृश्य धागे, जो हमें किसी नए द्वार तक ले जाने के लिए आए थे। यह अनुभव हमारी चेतना का विस्तार करते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> जीवन में जो अनुभव हमें मिलते हैं, वे एक मौन शिक्षक की तरह काम करते हैं। ये अनुभव, जो हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराते हैं, हमारी धैर्य-शक्ति को परखते हैं और हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। समय के साथ हम यह समझने लगते हैं कि सुख और दुख दोनों ही क्षणभंगुर हैं और इनका चक्र जीवन भर चलता रहेगा।

कभी अचानक ऐसे मोड़ भी सामने आ खड़े होते हैं, जिनसे निकलने के लिए मन व्याकुल हो उठता है। यह व्याकुलता, संघर्ष और इनसे उपजे अनुभव मिलकर हमारे भीतर एक गठरी बना देते हैं- अनुभवों की गठरी। यही गठरी हमें संभालती भी है और हमें परिपक्व भी बनाती है। शुरू में जो उतार-चढ़ाव हमें तोड़ने लगते हैं, वही अनुभव धीरे-धीरे हमें इस धारा के प्रवाह को स्वीकार करना सिखा देते हैं। मानव जीवन एक सतत यात्रा है, जो केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। इसका मूल उद्देश्य आत्मा को उस विद्वता और शांति के आलिंगन तक ले जाना है, जहां वह परमात्मा में विलीन हो सके। यह यात्रा रैखिक नहीं है। यह समय और जन्म की परतों में फैली हुई है। हर अनुभव अधूरे पाठों को पूरा करने की एक कड़ी भर है। हमारे जीवन में आने वाले सुख-दुख, रिश्ते-नाते, सफलताएं और असफलताएं, सब हमारे लिए अनुबंध होते हैं, जिन्हें पूरा करना हमारी नियति होती है। कई बार ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि हमें लगता है जैसे हम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हैं, जो हमें किसी निश्चित दिशा में खींच रही है। कभी ये अनुबंध पीड़ा के रूप में सामने आते हैं- किसी रिश्ते की कसक, किसी प्रियजन का बिछोह या किसी असफलता का बोझ बनकर। कभी ये सामाजिक या पारिवारिक रूप में प्रकट होते हैं, जहां हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है या किसी गहरे रिश्ते के माध्यम से हमें कोई महत्त्वपूर्ण सबक मिलना होता है। जब हम इन अनुबंधों की गहराई को समझना शुरू करते हैं, तो जीवन का अर्थ बदलने लगता है। तब हमें यह अहसास होता है कि हर घटना, हर मोड़, हर सुख और दुख आत्मा की उन्नति के लिए एक साधन मात्र हैं।

जीवन में जो अनुभव हमें मिलते हैं, वे हमारे भीतर एक मौन शिक्षक की तरह काम करते हैं। ये अनुभव, जो हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराते हैं, हमारी धैर्य-शक्ति को परखते हैं और हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। समय के साथ हम यह समझने लगते हैं कि सुख और दुख दोनों ही क्षणभंगुर हैं और इनका चक्र जीवन भर चलता रहेगा। यह समझ हमें भीतर से स्थिर कर देती है। तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम प्रतिक्रियाशील होने के बजाय पर्यवेक्षक बन जाते हैं। यही पर्यवेक्षक दृष्टि हमें उस गहन शांति तक ले जाती है, जिसकी तलाश हर आत्मा अनजाने में करती रहती है।

अक्सर लोग इस अवस्था को उदासीनता कहकर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि व्यक्ति अब न खुशी महसूस करता है, न दर्द। लेकिन यह उदासीनता दरअसल वह शांति होती है, जो हर अनुभव को सहजता से स्वीकार करना सीख चुकी होती है। जब हम किसी घटना को केवल उसकी सतही रूपरेखा में देखते हैं, तो हमें उसमें या तो पीड़ा दिखती है या उल्लास। लेकिन जब हम उसे अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानकर देखते हैं, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तब न हम अत्यधिक उल्लसित होते हैं, न अत्यधिक व्यथित। हम बस उस घटना को एक अनुभव के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ जाते हैं। यही परिपक्वता है।

जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल जीना या भौतिक सुख-सुविधाओं का संग्रह करना नहीं है। ये तो यात्रा के बीच में मिलने वाले छोटे ठहराव भर हैं। असली लक्ष्य अहंकार का समाप्त हो जाना है, इच्छाओं का शांत हो जाना है। मगर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें नए सबक लिखे जाते हैं- कभी यह अध्याय सुखद होता है, कभी अत्यंत कठिन, लेकिन दोनों ही हमारी उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। जीवन की यह धारा निरंतर बहती रहती है, हम चाहें या न चाहें। हम इसके प्रवाह के साथ चलना सीख सकते हैं। जब हम इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। तब न हमें ठहराव की लालसा रहती है, न मोड़ों से डर। हम बस बहते जाते हैं, सीखते जाते हैं, और आखिर शांति के किनारे तक पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्ची यात्रा है- अनुभव से ज्ञान, ज्ञान से शांति, और शांति से मुक्ति की ओर एक सतत् प्रवाह।

आतंक का दायरा

राजधानी दिल्ली में लालकिला के पास एक कार में हुए धमाके की घटना ने एक बार फिर यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताजनक सवाल खड़ा किया है, वहीं इस बात को लेकर एक आशंका खड़ी हो रही है कि क्या आतंकवादी संगठनों ने दोबारा अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि कार में हुए धमाके को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है कि विस्फोट का कारण क्या था, इसलिए इसके पीछे की मंशा के बारे में तभी कुछ ठोस सामने आ सकेगा, जब सरकार की ओर से कराई जाने वाली जांच की आधिकारिक रपट कोई संकेत करेगी। मगर धमाके का स्वरूप और उससे होने वाले नुकसान का जो दायरा दिखा, वह बेहद चिंताजनक है। इसमें किसी व्यापक साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि सोमवार की शाम एक कार में हुए विस्फोट के बाद आसपास खड़े कई अन्य वाहन उसकी जद में आ गए और कई लोगों की जान चली गई। घटना स्थल से जानमाल के नुकसान के जैसे ब्योरे सामने आए, वे किसी बड़े आतंकवादी हमले या बम विस्फोट की तस्वीर से ज्यादा अलग नहीं थे।

जाहिर है, अब देश की जांच एजंसियां इस धमाके के बारे में विस्तृत पड़ताल कर सच्चाई का पता लगाएंगी। फिलहाल जांच के बिंदु में सभी कोण शामिल होने चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी में हुई यह घटना बेहद संवेदनशील है और कई तरह के खतरों का संकेत भी हो सकती है। यही वजह है कि इस मामले में यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और अन्य सख्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच का दायरा व्यापक रखा गया है। निश्चित रूप से इस धमाके की सभी कड़ियों की पड़ताल कर दोषियों को सजा के अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है, मगर सवाल यह भी उठता है कि राजधानी होने के नाते सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सबसे चौकस और बेहतर मानी जाने वाली दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई और सुरक्षा एजंसियों को इसके बारे में कोई अंदाजा तक नहीं हुआ, तो यह किसकी नाकामी है! इस घटना के तार एक दिन पहले आतंकी तंत्र के एक हिस्से के खुलासे के तहत फरीदाबाद में गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन कार में धमाके की वजह अगर कोई विस्फोटक था, तो उसे वाहन में लेकर कोई व्यक्ति बिना किसी रोकटोक के सड़क पर कैसे चलता रहा और क्या यह देश की खुफिया एजंसियों की कार्यशैली के चिंताजनक पहलू को नहीं दर्शाता है!

सबसे अहम है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चौतरफा चाकचौबंद बनाना, ताकि यहां के लोगों को अतीत की वैसी त्रासदी का सामना फिर से करने की नौबत कभी न आए, जब यहां सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और उसमें कई लोग मारे गए। आतंकी हमलों के वैसे दौर की वापसी न हो, इसके लिए सरकार को हर जरूरी कदम उठाने चाहिए। खासतौर पर किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश के पहलू से इस घटना की गहन छानबीन होनी चाहिए। सिर्फ दावे करने भर से आतंकवाद का खात्मा होना मुमकिन नहीं है। जम्मू-कश्मीर में आज भी आतंकियों की घुसपैठ और हमले की कोशिशें बताती हैं कि देश में आतंकवाद आज भी एक ऐसी चुनौती है, जिसे लेकर थोड़ी भी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सरकार की सबसे जरूरी प्राथमिकता यहां के आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसके लिए खुफिया एजंसियों सहित सुरक्षा व्यवस्था के सभी मोर्चों पर निरंतर चौकस रहने की जरूरत है।

आवारा सही पर दोस्त भरोसेमंद है!

शंभू नाथ शुक्ल

वर्ष 1960 में जब मेरी उम्र पांच वर्ष की थी, तब गांव में एक कुत्ते ने मुझे दौड़ाया और मेरी टांगों को सूंघा तथा वापस चला गया। लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। चाचा लोग घबड़ाये और तहसीलदार से मेरे लिए कुत्ता काटे का टीका लिखवा लाए। उन दिनों तहसीलदार की तस्दीक़ पर ही अस्पताल में 14 टीके लगाए जाते थे। एक-एक फ़िट लंबे ये टीके सिर्फ ज़िला अस्पतालों में लगते। पिताजी तब कानपुर शहर में रहते थे और मां तथा हम बच्चे गांव में। चाचा मुझे पिताजी के पास छोड़ गए। हर सप्ताह जब परेड अस्पताल जाते तो उस टीके का आकार देख कर रुलाई फूटती किंतु कोई चारा नहीं था। कम्पाउण्डर पेट में वह सुई घुसेड़ ही देता। पिताजी के काम पर जाने के बाद घर में अकेला रहता तो मूँगफलियाँ चबाया करता। कुछ दिनों बाद मेरी नींद ग़ायब हो गई और शरीर पीला पड़ने लगा। पिताजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (हैलट अस्पताल) ले गये तो पता चला कि मुझे कुत्ते ने काटा ही नहीं था। मगर तब तक सात इंजेक्शन लग चुके थे. अब चूंकि कुत्ते ने काटा नहीं था पर टीके लग गये, इसका ख़ामियाज़ा उस बालपन में भुगतना पड़ा। मुझे Epilepsy हो गई, घर वालों ने मेरे तालाब या नहर में अकेले जा कर नहाने पर रोक लगा दी। बचपन से ही नींद की गोली दी जाने लगी और आयरन के सिरप भी क्योंकि ब्लड में लाल रक्त कण कम हो गए थे। शरीर का इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया। कई महीने लगे मुझे चंगा होने में। इसके बाद से तो मैं कुत्तों से ऐसा डरने लगा कि किसी के घर यदि कुत्ता, डॉगी या कोई पॉपी पला है तो मैं भरसक कोशिश करता कि उसके घर न जाना पड़े। हालाँकि अब चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित है और कुत्ते काटने पर तीन या पांच सुइयाँ ही लगती हैं। कोई भी प्राइवेट डॉक्टर इन्हें लगा सकता है। पर आज से 65 वर्ष पहले कुत्ते द्वारा काट लेने का मतलब था हाइड्रोफोबिया का शिकार हो जाना। इसका मरीज़ बूँद-बूँद पानी को तरस कर मर जाता था। आज तो एंटी रैबीज डोज़ की टैबलेट्स भी आने लगी है।

कुत्ता और मनुष्य की दोस्ती पुरानी : मानव सभ्यता की शुरुआत से ही कुत्ते मनुष्य के दोस्त रहे हैं। संभवतः मनुष्य का पहला पालतू पशु कुत्ता ही था। जब कृषि सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य भी अन्य चौपायों की तरह छोटे जानवरों का शिकार करता। चूँकि उसके सिर्फ दो पाँव थे इसलिए दौड़ने की उसकी क्षमता बहुत कम थी। ऐसे में कुत्ते मनुष्य की मदद करते। वे झपट कर शिकार को दबोच लेते और अपने नुकीले दांतों तथा पंजों से उसे उधेड़ देते। मनुष्य को आग का ज्ञान था, इसलिए वह उस शिकार को भूनता और उसके मांस से अपना पेट भरता। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ें पालनी शुरू कीं तब यह कुत्ता ही उन भेड़ों और बकरियों की भेड़ियों से रक्षा करता। इसलिए कुत्ते के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना मुश्किल है। शायद इसी कारण हमारी पुराण गाथाओं में कुत्ता मनुष्य का भरोसेमंद मित्र बताया गया है।

महाभारत में कुत्ता : महाभारत में युधिष्ठिर के एक प्रिय पशु कुत्ते का वर्णन है। इस कुत्ते का नाम युधिष्ठिर ने धर्म रखा था। महाभारत में बताया गया है कि अनेक वर्षों तक राज करने के बाद जब पांडवों ने स्वर्गारिहण के बारे में सोचा, तब सभी भाइयों, द्रोपदी और अपने कुत्ते धर्म के साथ युधिष्ठिर सुमेरु पर्वत पर चढ़ते हुए स्वर्ग की तरफ़ जाने का अभियान करने लगे। इस कथा के अनुसार सबसे पहले द्रोपदी भूमि पर गिरी क्योंकि वे अपने पाँचों पतियों में से सिर्फ अर्जुन पर विशेष अनुरक्त रहती थी। उनके बाद सहदेव गिर पड़े क्योंकि उन्हें अपने पांडित्य पर अभिमान था। फिर नकुल का नम्बर आया। नकुल को अपने सुदर्शन होने पर गर्व था। अर्जुन गिरे क्योंकि अर्जुन को लगता था कि महाभारत युद्ध सिर्फ उनके और उनके धनुष गांडीव के बूते ही जीता गया। अंत में भीम भी गिर पड़े तो भीम ने युधिष्ठिर को पुकारा और पूछा, भैया बताते तो जाओ, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने बिना पलटे जवाब दिया क्योंकि तुम पेटू थे। लेकिन युधिष्ठिर और उनका कुत्ता सशरीर स्वर्ग लोक के दरवाज़े पर पहुंचे। स्वर्ग के राजा इंद्र ने उनकी सशरीर स्वर्ग में आने पर स्वागत हेतु रथ भेजा था। किंतु युधिष्ठिर ने उस रथ पर चढ़ने के लिए पहले अपने कुत्ते धर्म को आमंत्रित किया तो रथवान ने आपत्ति की। उसने कहा, नहीं महाराज स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। इतना सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भी रथ पर नहीं चढ़ूँगा। यह कुत्ता अपने धर्म (कर्तव्य) से कभी विचलित नहीं हुआ इसीलिए वह यहाँ तक सशरीर पहुँचा है। यदि इसे प्रवेश नहीं मिलेगा तो मैं भी स्वर्ग लोक में कदम नहीं रखूँगा। तब कुत्ते ने साक्षात धर्मराज का अपना स्वरूप दिखाया और कहा, युधिष्ठिर मैं तुम्हारे सत्य और धर्म की परीक्षा ले रहा था, तुम खरे उतरे हो। यह बोल कर वह कुत्ता विलीन हो गया।

रामायण में कुत्ता प्रसंग : इसी तरह रामायण में भी एक कुत्ते द्वारा राजा राम से न्याय माँगने का प्रसंग है। इस कथा में बताया गया है कि एक कुत्ता राजा राम के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हुए आता है और कहता है कि अमुक ब्राह्मण ने मुझे अकारण पत्थर से मारा है। महाराज मुझे न्याय दिया जाए। राजा रामचंद्र जी का सारा दरबार हतप्रभ। कुत्ते को न्याय देने के लिए ब्राह्मण को दंड! पर कुत्ता हठ किये था। अंत में राम ने पूछा हे श्वान श्रेष्ठ, यह तो बताओ इस ब्राह्मण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुत्ता कहता है, इसने मुझे पत्थर से मारा। राम जी ने उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, हां राजन मैंने इसे मारा। मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूँ, उस दिन मुझे भिक्षा नहीं मिली। मैं भूखा था तभी अचानक मुझे देख कर यह कुत्ता भौकने लगा, मुझे ग़ुस्सा आ गया और मैंने इसे पत्थर मारा राजा रामचंद्र ने कुत्ते से पूछा, कि तुम क्यों भौके? वह बोला, राजन भौकना तो मेरी प्रवृत्ति है, मेरा धर्म है। दरबार में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि कैसे न्याय किया जाए। अंत में रामचंद्र जी उस कुत्ते से पूछते हैं, तुम ही बताओ मैं इस कुत्ते को क्या दंड दूँ? वह कुत्ता कहता है, भगवन, इस ब्रह्मण को अमुक मठ का महंत बना दीजिए। पूरा दरबार चौक गया। कुत्ता कैसा न्याय चाह रहा है! बाद में वह कुत्ता कहता है, प्रभु मैं पिछले जन्म में उसी मठ का महंत था। मैंने वहाँ रह कर लोक कल्याण का कोई काम नहीं किया। बस खाता और मस्त पड़ा रहता, नतीजा इस जन्म में मुझे कुत्ते की योनि मिली। ये दोनों मिथकीय कथाएँ है।

कुत्ते की जगह पर मनुष्य ने क़ब्ज़ा किया! : जो लोग कुत्ते के मनोविज्ञान को समझते है, उनका कहना है कि कुत्तों में मनुष्य की तुलना में आसन्न संकट को समझ पाने की क्षमता अधिक होती है। उसकी सूंघने की शक्ति तीव्र है, वह ध्वनि तरंगों को पकड़ लेता है। इसके अलावा वह भौक कर अपनी क्षेत्रीय सीमा भी बताता है कि यह उसकी सीमा है और इसमें कोई और अतिक्रमण कर रहा है। लेकिन पशु चिकित्सक डॉ. जेबी सिंह बताते है कि कुत्ते ने कभी यदि कभी आपकी गाड़ी पर पेशाब किया है, तो जब भी वह गाड़ी उसके क़रीब से गुजरेगी वह उस गाड़ी के पीछे भागेगा। एक कुत्ते को दिन भर में 25 किमी की दौड़ उसके शरीर के अनुसार अनिवार्य है।

फ़्लैट में कुत्ता और रौद्र होगा : आजकल महानगरों में फ़्लैट्स में रहने वाले लोग भी पाल लेते हैं। सीमित दायरे के फ़्लैट में क़ैद कुत्ते अजनबी को देखते ही झपट पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुत्ते जैसा पेट (पालतू पशु) कभी भी लिफ़्ट पर चढ़ने का आदी नहीं होता और अक्सर वह लिफ़्ट में हिंसक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट मोहल्लों में बढ़ते स्ट्रीट डॉग को ले कर चिंतित है। यह अच्छी बात है मगर स्ट्रीट डॉग म्यूनिस्पैलिटी की समस्या है। और देश की किसी भी म्यूनिस्पैलिटी ने इस समस्या को ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं किया। कुत्तों को मार देने से या उन्हें शेल्टर होम में क़ैद करने से कुत्तों की संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी।

पेट्स की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए : कुत्तों को बधिया करना समस्या एक हल है किंतु म्यूनिस्पैलिटी इस पर अमल करेगी, इस पर संदेह है। कुत्ता प्रेमी जन कुत्तों को केतु का अवतार मानते है और उनके सफ़ायें में यह धार्मिक ख़याल आड़े आता है। कुछ लोग स्ट्रीट डॉग को रोटी या बिस्किट्स डालते रहते है, इसलिए कुत्ता परक जाता है। ऐसे में यदि वह भूखा हुआ और कोई भी शख़्स स्ट्रीट डॉग के झुंड के बीच से निकला तो वे हमलावर हो उठते है। अमेरिका, कनाडा और योरोप के देशों ने कुत्तों से निजात पाने के लिए स्ट्रीट डॉग को बधिया कर दिया। चूँकि कुत्ते की उमर 12-13 साल की ही होती है, इसलिए धीरे-धीरे उनकी संख्या घटने लगी। अलबत्ता वहाँ घरों में लोग कुत्ते पालते है, पर उन्हें कुत्ते की पूरी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है।

लुटियन ज़ोन में भी आवारा कुत्ते : इसलिए वहाँ कुत्ते अब समस्या नहीं रहे। सर्वाधिक मुश्किल था, चीन में। जहां कुत्तों के कारण शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में रात-बिरात निकलना मुश्किल था। मगर वहाँ अब कहीं भी स्ट्रीट डॉग नहीं दिखते। यद्यपि लुटियन ज़ोन में आवारा कुत्तों की गिनती कभी नहीं की गई, पर वहाँ रहने वाले ऐसी शिकायत करते रहते है।

Rashtriya Sahara Page No-6

ऐसी दहशतगर्दी हमारी परीक्षा लेती रहेगी

राजधानी दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर कार धमाके की घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, हालांकि इस तरह की वारदातों को पूरी तरह रोक पाना काफी मुश्किल काम है। इस विस्फोट की तीव्रता इतनी भयावह थी कि आसपास की दुकानों के शीशे तक चूर-चूर हो गए और आग की लपटों ने कुछ पलों के लिए पूरे क्षेत्र को अंधेरे में डूबो दिया। इस विस्फोट की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें मौके पर पहुंच गईं, जो बताता है कि हमारी सुरक्षा व खुफिया तत्पर हैं और पूरी तरह सक्षम भी। गौरतलब है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां रोजाना लाखों लोग आते-जाते हैं। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि पर्यटन और व्यापार का केंद्र भी है। इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह का सुनियोजित हमला संकेत है कि असामाजिक तत्व फिर से सक्रिय होने लगे हैं। इससे स्वाभाविक ही आम जनता में दहशत का माहौल है, लेकिन ऐसी वारदातों से भारत रुकता नहीं है। यह घटना भले ही लोगों में आक्रोश पैदा करे, लेकिन इस समय संयम बरतना और एकजुट बने रहना बेहद जरूरी है। हमें अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए। यह कायराना, दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहलाने वाली घटना है, जो भारत-विरोधियों की नापाक मंशा को उजागर करती है। हमें उनके खिलाफ पूरी ताकत से प्रतिरोध करना होगा और अपने सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

यह सही है कि बीते कुछ समय से आतंकी वारदातों में काफी कमी आई है और हमारे सुरक्षा बल लगातार आतंकियों से सफलतापूर्वक मोर्चा लेते रहे हैं, लेकिन सच यह भी है कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में दहशतगर्दी का खतरा शायद ही खत्म हो। इसकी वजह यह भी है कि देश के पास एक विशाल आबादी है और इसकी सीमाएं पूरी तरह से बंद नहीं हैं। फिर भी, हमारे सुरक्षा बलों की तारीफ करनी चाहिए कि वे आतंकियों को आमतौर पर रोक देते हैं। रविवार और सोमवार को ही फरीदाबाद में करीब तीन हजार किलो विस्फोटक की बरामदगी बताती है कि हमारी एजेंसियां सावधान रहती हैं। हां, यह अलग बात है कि सोमवार को दिल्ली में धमाका हो गया। मगर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, उम्मीद करनी चाहिए कि षड्यंत्रकारी जल्द बेनकाब होंगे।

रोहित कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

दिल्ली धमाका

Hindustan Page No-15

बढ़ता बिहार व बदलता चुनावी एजेंडा

बिहार चुनाव

संजय त्रिपाठी

बिहार की धरती एक बार फिर राजनीतिक इतिहास के निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। इस बार के विधानसभा चुनाव ने न केवल नेताओं और दलों को बल्कि पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। आजादी के बाद पहली बार राज्य में मतदान प्रतिशत में इतनी बड़ी छलांग देखी गई है। गांव-गांव,शहर-शहर मतदाताओं की अभूतपूर्व सक्रियता ने यह साबित कर दिया कि बिहार अब केवल राजनीति का उपभोक्ता नहीं, बल्कि परिवर्तन का निर्माता बन चुका है। यह केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चेतना का उदय है।

मतदान का उत्सव और जनता की जागरूकता : बिहार की जनता ने इस बार जो उत्साह दिखाया है, वह अभूतपूर्व है। लंबी कतारें,. इन सबके बावजूद मतदान प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। इस बार महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचीं। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि वे लोकतंत्र में भाग ले रही हैं, बल्कि यह कि वे अब अपने जीवन की प्राथमिकताओं को खुद तय करना चाहती हैं।

युवाओं ने भी इस बार अभूतपूर्व भागीदारी की। एक समय था जब बिहार के युवा मतदान के बजाय पलायन को प्राथमिकता देते थे। लेकिन अब वे लौट रहे हैं, मतदान कर रहे है और अपने राज्य के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। मजदूर वर्ग ने भी अपने मौन से व्यवस्था को हिलाया है। यह वही वर्ग है जो दशकों से रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में भटकता रहा, पर अब उसने अपने "मत" से संदेश दिया है कि "हमारा जीवन अब दूसरों की नीतियों पर नहीं चलेगा।"

यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह उस असंतोष का परिणाम है जो पिछले कई दशकों से धीरे-धीरे सुलग रहा था। लाखों बेरोजगार युवा, शिक्षक अभ्यर्थी, ठेके पर काम करने वाले मजदूर और पलायन से टूटे परिवार अब अपने दर्द को "मुद्दे" में बदल रहे हैं। यह एक बड़ी सामाजिक क्रांति का संकेत है।

बिहार की जनता अब यह समझ चुकी है कि जातीय नारे और भावनात्मक भाषण केवल चुनाव जीतने का हथियार हैं, शासन सुधारने का नहीं। यही कारण है कि इस बार मतदाता ने "नेता की जाति" नहीं, बल्कि "नीति की गुणवत्ता" को देखा है।

जनसुराज की एंट्री- राजनीति में एक नया प्रयोग : इस बार के चुनाव ने एक नया नाम उभारा है . जनसुराज। प्रशांत किशोर द्वारा संचालित यह अभियान न किसी पारंपरिक दल का हिस्सा है, न किसी जातीय गठबंधन का। इसके बावजूद, इसने बिहार के राजनीतिक समीकरणों में अभूतपूर्व हलचल मचा दी है। जनसुराज की असली ताकत उसके विचार की सादगी और संदेश की स्पष्टता में है। रोजगार, शिक्षा और पलायन-तीन ऐसे मुद्दे जिन्हें वर्षों से हर सरकार ने अपने घोषणापत्र में तो रखा, पर कभी प्राथमिकता नही दी। जनसुराज ने इन मुद्दों को केवल भाषण में नहीं, बल्कि जनता के संवाद में शामिल किया। गांव-गांव में प्रशांत किशोर की "जनसंवाद यात्रा" ने यह साबित किया कि जनता आज भी उन नेताओं को सुनना चाहती है जो उसके बीच जाते है, जो उसकी भाषा बोलते है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार,

जनसुराज ने बिहार में एक नई "आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स" की नीव रखी है . जो न हिंदू-मुस्लिम में बंटी है, न जातीय खांचों में। इसने यह दिखाया कि बिहार अब "राजनीतिक ठेकेदारों" से आगे बढ़कर "नीतिगत विकल्पों" की तलाश में है।

मतदाता का बदला हुआ मनोविज्ञान : बिहार के इस चुनाव की एक बड़ी विशेषता है मतदाताओं की चुप्पी। यह चुप्पी सामान्य नहीं थी . यह गहरी सोच का प्रतीक थी। लोग खुलकर यह नहीं बता रहे थे कि वे किसे वोट देंगे, लेकिन उनके सवाल साफ थे- "रोजगार कहां है?", "शिक्षा क्यों पिछड़ी?",उन्हें सरकार से अधिक की आशा है ?"

मतदाता अब केवल सरकार गिराने के लिए वोट नहीं दे रहा, बल्कि यह तय करने के लिए वोट दे रहा है कि राज्य किस दिशा में जाएगा। बिहार की यह चुप्पी सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ा भय बन चुकी है, क्योंकि इस चुप्पी में "सजगता" छिपी है।

जनादेश का दूरगामी प्रभाव- 2029 की छाया : इस बार का बिहार चुनाव केवल एक राज्यीय मुकाबला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव बन सकता है।

वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव पर इस जनादेश का असर निश्चित रूप से पड़ेगा। बिहार हमेशा से भारतीय राजनीति का बैरोमीटर रहा है । यहां का रुझान पूरे देश के मूड को प्रभावित करता है। 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर 1990 में लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के उभार तक, हर युग की शुरुआत बिहार से हुई। अब यदि 2025 में बिहार फिर करवट लेता है, तो 2029 में देश की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो सकता है।

महिलाएं और युवा-लोकतंत्र की नई रीढ़ : इस बार के मतदान में महिलाओं और युवाओं की भूमिका निर्णायक रही है। बिहार की महिलाएं पहले भी मतदान में सक्रिय थीं, लेकिन इस बार उन्होंने "सत्ता-परिवर्तन" नहीं, बल्कि "सोच-परिवर्तन" का संदेश दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और सुरक्षा जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिकता में है। वही युवा पीढ़ी, जो पहले राजनीति से निराश थी, अब सक्रिय भूमिका में है। वे अब "नौकरी की मांग" को राजनीति के केंद्र में ला रहे है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक, युवा अब एजेंडा तय कर रहे है। यही कारण है कि पारंपरिक दलों के लिए यह चुनाव सहज नहीं रहा।

यह चुनाव सोच का चुनाव है : बिहार का यह चुनाव किसी सरकार को गिराने या बनाने का नही, बल्कि सोच बदलने का चुनाव है। यह उस जनता का जनादेश है जिसने यह तय कर लिया है कि अब केवल वादों से नही, बल्कि कार्य से आंका जाएगा। अब "नाम" नहीं, "काम" चलेगा। जनसुराज का उभार, महिलाओं का बढ़ता मतदान, युवाओं की भागीदारी, जाति समीकरण का टूटना,ये सब संकेत है कि बिहार अब एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर चुका है।

जागता बिहार : चौदह नवंबर को जब नतीजे आएंगे, तो यह स्पष्ट होगा कि जनसुराज ने क्या पाया और क्या खोया। पर एक बात निश्चित है कि बिहार की जनता अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने वोट से एक स्पष्ट संदेश दिया है ।"हम अब जाग चुके हैं।" यह चुनाव दिखाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता में नहीं, जनता की समझ में है। जब जनता अपने मुद्दे खुद तय करती है, तो लोकतंत्र जीवित रहता है।

लोकतंत्र में असली सुराज तभी आएगा जब जनता अपने मुद्दों को खुद तय करेगी। और इस बार बिहार ने वही कर दिखाया है।

Prabhat khabar Page No-12

सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर उठेंगे

भारत की यह विडंबना ही है। यहां पता नहीं चलता कि कब ,कौन और कहां काल का शिकार बन जाए! अति-सुरक्षित कहे जाने वाले क्षेत्र में भी यदि विस्फोट की घटना हो जाए, तो समझा जा सकता है कि स्थिति क्या है? देश की राजधानी और दिलवालों की नगरी कही जाने वाली दिल्ली के एक महत्वपूर्ण इलाके में कार विस्फोट हुआ, जिसने जान-माल की बड़ी हानि पहुंचाई। यह घटना ऐतिहासिक लाल किले के ठीक बगल में हुई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे दिल दहला रही हैं। सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली की सख्त और चौकस सुरक्षा-व्यवस्था में दहशतगर्दों ने सेंध कैसे लगा दी? क्या यह हमारी खुफिया एजेंसियों की नाकामी का नतीजा है? अगर यह विस्फोटक से किया गया हमला है, तो राष्ट्रीय राजधानी में इसे कैसे लाया गया? निस्संदेह, इस मामले की जांच-पड़ताल से पूरी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन यह समझना होगा कि जिन निर्दोषों की जान ऐसे हादसों में चली जाती है, उसकी भरपायी महज मुआवजे से नहीं हो सकती। अगर घटनाएं घट रही हैं, तो सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर ही उठेंगे। अब खबर यह भी है कि दिल्ली धमाके के तार फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी और पुलवामा हमले से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर यह सच हो, तो पहले क्यों नहीं इसका पता लगाया जा सका और समय रहते इसको निष्क्रिय किया जा सका? खैर, यह हादसा दर्दनाक है और समय का तकाजा है कि जो भी दोषी हैं, उनको तत्काल सजा दी जाए, ताकि भविष्य में भारत का कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिमाकत न कर सके।

हर्षवर्द्धन कुमार, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली जगह पर एक कार में विस्फोट हुआ और कई लोगों की जान चली गई। कई घायल भी हुए हैं। निश्चय ही, यह कोई पहली घटना नहीं है, जो सुरक्षित क्षेत्र में हुई है। इससे पहले भी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व खुफिया बलों को चकमा देकर आतंकी अपनी मंशा में सफल होते रहे हैं। मगर इस बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि माना यही जाता है कि देश मजबूत हाथों में है। क्या सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए? आखिर भारतीय सुरक्षा तंत्र में कहां खामी थी? क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों में कोई कमी थी? क्योंकि सरकार इसके लिए उचित रणनीति नहीं बना पा रही? इन सभी सवालों के जवाब हमें ढूंढ़ने होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-12

शाबाश बिहार

दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही बिहार में 2,600 से अधिक प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। यह बेहद संतोष की बात है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, बल्कि जिस बड़े पैमाने पर राज्य के मतदाता दूसरे चरण में भी मतदान केंद्रों पर उमड़े, वह बिहार की चुनावी तारीख में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। चुनाव आयोग अंतिम आंकड़ा तो बाद में दर्ज करेगा, मगर तीन बजे तक ही किशनगंज, बांका, कटिहार, पूर्णिया, जमुई आदि जिलों में 63 प्रतिशत से अधिक मतदान की सूचना से यह साफ हो गया था कि बिहार अपने सर्वाधिक मतदान की पटकथा लिख चुका है। जिस तरह, पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई और उसके बाद राज्य का राजनीति माहौल गरमाया, उसे देखते हुए यह अंदेशा था कि कहीं एक बार फिर बिहार दशकों पहले के उस शर्मनाक दौर में न पहुंच जाए, जब चुनावी हिंसा उसकी राजनीतिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। मगर चुनाव आयोग, राज्य प्रशासन और तमाम राजनीतिक दलों की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने हालात को बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मतदाताओं को प्रेरित किया कि वे बेखौफ होकर अपना नागरिक कर्तव्य निभाएं।

हिंदी पट्टी को लेकर यह आम शिकायत रही है कि यहां के मतदाता मतदान को अहमियत नहीं देते और अपना लोकतांत्रिक दायित्व निभाने से कतराते हैं। ऐसे में, बिहार का नया मतदान कीर्तिमान इस छवि को अवश्य बदलने का काम करेगा। पहले चरण में ही राज्य में 64.66 प्रतिशत की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल झारखंड में भी 67.62 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि इसके पांच वर्ष पहले यहां करीब 65 प्रतिशत वोट पड़े थे। बिहार का यह संदेश उत्तर प्रदेश तक बखूबी पहुंचना चाहिए, जहां 2017 के मुकाबले 2022 में करीब चार प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। वहां 2027 की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। यह एक स्थापित तथ्य है कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों की अधिकतम भागीदारी से सुनिश्चित होती है, ऐसे में कम मतदान प्रतिशत उसकी वैधता को नैतिक आधार से वंचित कर देता है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का यह दायित्व बनता है कि वे मतदाताओं के इस उत्साह को मंद नहीं पड़ने दें।

हिंदी पट्टी को लेकर यह शिकायत रही है कि यहां के मतदाता अपना लोकतांत्रिक दायित्व निभाने से कतराते हैं। ऐसे में, बिहार का नया मतदान कीर्तिमान इस छवि को बदलेगा।

बिहार विधानसभा का यह चुनाव इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि चुनाव से ऐन पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) चलाया और उसकी इस कवायद से उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से शांत हुआ, बल्कि इस एसआईआर पर शीर्ष अदालत का आखिरी फैसला अभी आया भी नहीं है और वहां मतदान संपन्न हो चुका है। इस पूरे विवाद ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक दल ही नहीं, मतदाताओं के मन में भी तमाम तरह के सवाल पैदा किए। इसलिए मुनासिब यही है कि बिहार के रिकॉर्ड मतदान को यह सांविधानिक संस्था अपनी छवि पर मुहर के रूप में न ले, बल्कि इसकी एक व्याख्या मतदाताओं की प्रतिक्रिया के रूप में भी की जाएगी। एक तथ्य यह भी है कि इस बार बहुत सारे मतदाता छठ पूजा के लिए अपने गांव-घर पहुंचे और मतदान के लिए रुक गए थे। बेहतर होगा कि आयोग इस उत्साह को अपनी सकारात्मक पहल से आगे ले जाए।

डिजिटल जहर से समाज को बचाने की अनूठी पहल

यहां स्कैन करें

किंशुक पाठक | एसोशिएट प्रोफेसर,पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

महाराष्ट्र के सांगली जनपद के मोहित्यांचे वडगांव (जिसे संक्षेप में वडगांव कहा जाता है) में हर शाम सात बजे भैरवनाथ मंदिर से 45 सेकंड के लिए एक सायरन-ध्वनि गूंजती है, जो किसी चीनी मिल या अन्य औद्योगिक इकाई के कर्मचारियों के लिए बजने वाले सायरन से भिन्न है। यह ध्वनि दरअसल एक सूचना है कि अगले 90 मिनट (7 से 8:30 बजे तक) सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-मोबाइल, टीवी इत्यादि बंद रहेंगे। दूसरा बजने वाला सायरन इस अवधि की समाप्ति की सूचना देता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षेत्रवार समूहों का गठन किया गया है, जो हर घर जाकर इस पहल का महत्व समझाते हैं। इस 'डिजिटल कर्फ्यू' का उल्लंघन करने वालों को शुरू में चेतावनी दी जाती थी, लेकिन अब पूरा समाज इसका पालन करने का प्रयास करता है। माता-पिता भी नियम का अनुपालन करते हैं, ताकि बच्चे अकेला न अनुभव करें। इस 90 मिनट में बच्चे अध्ययन करते हैं, युवा पुस्तकें पढ़ते हैं या घर से बाहर निकलकर सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं।

वर्तमान दौर में स्मार्टफोन और टीवी हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं, पर वडगांव ने इसको चुनौती दी है। इस गांव में लगभग 3,000 से 3,500 लोग रहते हैं। अधिकतर किसान या चीनी मिल श्रमिक हैं, जो प्रत्येक शाम डेढ़ घंटे के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का पालन करते हैं। 15 अगस्त, 2022 को देश के स्वतंत्रता दिवस पर प्रारंभ हुई यह पहल अब न केवल ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, बल्कि आस-पास के गांवों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गई है।

महाराष्ट्र के वडगांव में हर रोज पूरे डेढ़ घंटे तक कोई भी व्यक्ति मोबाइल, टीवी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं चलाता।

दरअसल, कोविड-19 के संक्रमण-काल में मानव व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन देखा गया। इसने 2020 से 2022 तक शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम को अनिवार्य बना दिया, जिससे कम आयु के बच्चों और युवाओं में मोबाइल फोन के प्रयोग को लेकर एक बुरे व्यवहार ने जन्म लिया। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के 65 प्रतिशत बच्चों में फोन चलाते रहने की मानो लत पड़ गई, जो 30 मिनट से अधिक समय तक फोन से दूर रहने में असमर्थ थे।

वडगांव के सरकारी विद्यालयों में भी बच्चे कक्षाओं में एकाग्र नहीं रह पा रहे थे; वे निरंतर वीडियो देखने या सोशल मीडिया में खोए रहते। तब इतिहास के शिक्षक जयवंत विट्ठल मोहिते जैसे कई सेवानिवृत्त शिक्षकों ने इस समस्या को समझा और और इसके नुकसान का अनुमान लगाया। सबके प्रयास से गांव के मुखिया विजय मोहिते ने अगस्त 2022 में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और सार्वजनिक घोषणा की कि 'डिजिटल विष' से अपने समाज को बचाना है और स्वतंत्रता दिवस पर इस मुहिम को अंजाम दे दिया गया। जिला विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कर्मी, आशा कार्यकर्ता व स्थानीय महिलाओं के सामूहिक सहयोग से इस मुहिम का कार्यान्वयन हुआ और लक्ष्य की प्राप्ति हुई।

मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का अत्यधिक उपयोग एकाग्रता, बौद्धिक ह्रास, भावनात्मक व्यवहार और रचनात्मकता को प्रभावित करता है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अनुसार, लगभग एक-तिहाई नाबालिग बच्चे मोबाइल से होने वाले दुष्परिणामों से प्रभावित हैं। ऐसे में, 'डिजिटल डिटॉक्स' पहल का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास है।

जब लक्ष्य सकारात्मक बदलाव का हो, तब समाज भी साथ आ खड़ा होता है। डिजिटल डिटॉक्स मुहिम का परिणाम यह हुआ कि एक माह में ही अंतर साफ दिखने लगा। छात्रों के अध्ययन में सुधार हुआ, रचनात्मकता में वृद्धि हुई और स्कूल में उनके व्यवहार में और स्पष्ट बदलाव नोटिस किया गया। इन नतीजों को ध्यान में रखते हुए सरपंच विजय मोहिते ने अब इसे ढाई घंटे तक करने का विचार किया है। सांगली जिले के पांच अन्य गांवों ने भी इसे अपनाया है, जो इसकी सफलता का प्रमाण है।

जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया विस्तृत हो रही है, वडगांव मॉडल जैसे प्रयोगों की अहमियत बढ़ती जा रही है। समाज को फिर से जोड़ने और संबंधों को पुनर्जीवित करने में ये रामबाण बन सकते हैं। इस पहल ने एक बार फिर हमें स्मरण कराया है कि तकनीक मनुष्य की सहजता के लिए है, न कि स्वामी बनने के लिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अब वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजर

अरुण कुमार | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

तनख्वाह बढ़ने से कुछ लोगों के हाथों में पैसे आ जाते हैं और बाजार में नकदी बढ़ जाती है, पर केंद्रीय बजट में घाटा भी बढ़ जाता है। इससे निपटने के उपाय भी करने होंगे।

इन दिनों आठवें वेतन आयोग को लेकर देश में हलचल तेज है। इसके 'टर्म ऑफ रेफरेंस', यानी आयोग के कामकाज की शर्तें और सीमाएं बताने वाले दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। मगर, आरोप यह भी लग रहे हैं कि सातवें और आठवें वेतन आयोग की शर्तों में अंतर है, जिसके कारण 69 लाख पेंशनभोगी इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।

हालांकि, एक बहस आयोग की सिफारिशों का देश के श्रम-बल और यहां की आर्थिकी पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चल रही है। यह सच है कि तकरीबन हर दस साल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है, क्योंकि सरकार मानती है कि अगर महंगाई के हिसाब से तनख्वाह में बढ़ोतरी न हो, तो कर्मचारियों के जीवन-स्तर में गिरावट आती है। यह एक अच्छी सोच है। मगर ऐसी सिफारिशें सरकारी खजाने पर बोझ भी बढ़ाती हैं। संभवतः इसीलिए, इस बार आयोग के सामने यह शर्त रखी गई है कि वह ऐसी सिफारिशें न दे, जिनसे सरकार का आर्थिक घाटा और बढ़ जाए।

सुखद यह है कि अपने यहां राजस्व खर्च (वेतन आदि पर सरकार का खर्च) बहुत अधिक नहीं है। यह कुल बजट खर्च का औसतन सात प्रतिशत है। फिर, तमाम सरकारी खर्च गैर-उत्पादक नहीं माने जाते। मसलन, रेलवे, डाक और दूरसंचार आदि अनिवार्य सेवाएं हैं, इसलिए यहां वेतन पर जो खर्च होता है, वे उत्पादक होते हैं। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर किया जाने वाला खर्च भी अनिवार्य है। इसका मतलब है कि दफ्तरों में कथित 'बाबुओं' की संख्या ज्यादा नहीं है। इसीलिए, अगर वेतन आयोग सिफारिशें करता भी है, तो सरकार पर उत्पादक खर्च का दबाव बढ़ेगा, गैर-उत्पादक खर्च का ज्यादा नहीं।

फिर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.12 प्रतिशत है, इस कारण कुल वेतन में सरकारी क्षेत्र का योगदान 39 प्रतिशत है। यह दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। मसलन, जीडीपी में सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी अमेरिका में 36.28 प्रतिशत है, फ्रांस में तो 56.99 प्रतिशत और जापान में 41.16 प्रतिशत। इसका अर्थ है कि अन्य देशों में हर एक लाख आबादी पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या भारत की तुलना में काफी ज्यादा है। भारत में करीब 1.8 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, जो कुल श्रमबल का 3.5 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसके बरअक्स संगठित कार्यबल का आधा हिस्सा निजी क्षेत्र में काम करता है, जहां वेतन आयोग की सिफारिशें परोक्ष रूप से असर डालती हैं।

देखा जाए, तो यही वह मुकाम है, जहां वेतन आयोग को लेकर संगठित क्षेत्र बनाम असंगठित क्षेत्र की बहस खड़ी की जाती है। यह तर्क दिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक है। चूंकि निजी क्षेत्र की मंशा अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की होती है, इसलिए यहां कर्मचारियों पर कई तरह के दबाव होते हैं। हालांकि, इसकी भरपायी वेतन-वृद्धि से करने की कोशिश भी की जाती है, जैसे- ज्यादा कर्मचारियों के बजाय कम कर्मियों की नियुक्ति करके उनको सामान्य से अधिक तनख्वाह देना। साथ ही, नियमित कर्मचारियों की जगह अनुबंध पर कामगार भी रखे जाते हैं। मगर इस कारण निजी क्षेत्र में असमानता भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।

इससे पार पाना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए जरूरी है कि हरेक कर्मचारी को कम से कम जीवन गुजारने लायक वेतन मिले। और, यह तब होगा, जब उसके पास काम होगा, क्योंकि रोजगार की कमी की वजह से ही असंगठित क्षेत्र के कर्मी अपने लिए बेहतर वेतन की मांग नहीं कर पाते, जबकि सरकारी कर्मियों के पास अपनी मांग पर जोर देने के लिए धरना या हड़ताल जैसे विकल्प होते हैं।

वेतन आयोग का एक असर अर्थव्यवस्था पर यह भी होता है कि अचानक उसमें मांग बढ़ जाती है। मुझे याद है, वर्ष 2006-07 में जब छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं, तब शिक्षकों को तीन-चार लाख रुपये अतिरिक्त मिल गए थे, जिससे उन्होंने कई तरह (कार, टीवी आदि) की खरीदारी की थी। इसी तरह की खरीदारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद भी संभव है। हालांकि, इस लाभ को बनाए रखने के लिए असंगठित क्षेत्र के मुलाजिमों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जीवन-स्तर में असमानता होने के कारण निजी क्षेत्र की तरफ से बाजार में मांग कम बढ़ती है, जिससे कुछ दिनों के बाद ही संगठित क्षेत्र की बढ़ी हुई मांग पूर्ववत स्तर पर आ जाती है। इतना ही नहीं, मांग बढ़ते ही कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ा देती हैं, जिससे महंगाई में इजाफा होता है। साल 2006-07 में भी ऐसा ही हुआ था।

बेशक, तनख्वाह बढ़ने से कुछ लोगों के हाथों में पैसे आ जाते हैं और बाजार में नकदी बढ़ जाती है, लेकिन केंद्रीय बजट में घाटा भी बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए काले धन की व्यवस्था पर दबिश एक विकल्प हो सकता है। दरअसल, प्रत्यक्ष कर जीडीपी का कमोबेश 6.5 प्रतिशत है। अगर काला धन का कारोबार कम हो जाए, तो यह हिस्सेदारी बढ़कर 15-16 प्रतिशत हो सकती है। इस कारण, वेतन-वृद्धि से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार को आसानी से टाला जा सकता है।

इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार होना चाहिए। मसलन, अभी आयकर विभाग के पास पांच से छह हजार अधिकारी हैं। अधिकारियों की यह संख्या तब से है, जब आयकर जमा करने वाली आबादी बमुश्किल दो से तीन करोड़ थी। अब इसमें भारी वृद्धि हो चुकी है और तकरीबन 9.5 करोड़ लोग आयकर जमा करने लगे हैं। इसका मतलब है कि दो-तीन करोड़ लोगों के आयकर को जांचने के लिए जितने कर्मी उचित माने गए थे, उतने ही आज 9.5 करोड़ लोगों के आयकर जांच रहे हैं। बेशक, अब कंप्यूटरीकरण हो चुका है, लेकिन काली कमाई करने वाली आबादी को पकड़ने के लिए, जो एक से दो फीसदी है, और अधिक अधिकारियों की दरकार है।

जाहिर है, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रम-बल के अंतर पर काम करने की जरूरत है। अगर इसमें कुछ सुधार हो जाए, तो वेतन आयोग की सिफारिशों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। यह सरकारी बनाम निजी क्षेत्र या संगठित बनाम असंगठित क्षेत्र का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पूंजी और श्रम के बीच का टकराव है। इसी वजह से यह पूरी व्यवस्था जटिल हो जाती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Page No-12